शनिवार

11 जुलाई 2026

● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 168
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

15 लाख की ठगी

पूर्व मुख्य सचिव के बेटे पर एफआईआर

हमारे संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस. रामास्वामी के बेटे यशोवर्धन के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में 15 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी और फर्जी पहचान बताकर ठगी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने पूर्व समय में पूर्व विधायक चैम्पियन के बेटे पर भी धौंस जमाई थी।

गढ़ी कैंट निवासी अंशुल उपाध्याय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी मुलाकात मार्च 2026 में यशोवर्धन से हुई थी। शिकायत के अनुसार, यशोवर्धन ने स्वयं को केंद्र सरकार की गुप्त एजेंसियों तथा स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप से जुड़ा अधिकारी बताते हुए अपने प्रभाव का दावा किया। आरोप है कि यशोवर्धन ने उनकी दिवंगत मां के नाम पर 'सुमन हेल्थ एंड ब्लेसिंग्स', 'हाउज द होस' और 'यूरेका फ्राग्स' नाम से कंपनियां पंजीकृत कराने का प्रस्ताव दिया। साथ ही यह भरोसा दिलाया कि स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत प्रत्येक कंपनी को 20 से 25 लाख रुपये तक की फंडिंग दिलाई जाएगी। तहरीर के अनुसार, आरोपी ने राजपुर रोड स्थित एक होटल में बुलाकर कंपनी पंजीकरण के नाम पर प्रति कंपनी 36 हजार रुपये लिए। इसके अलावा कस्टम विभाग से कम कीमत पर आईफोन उपलब्ध कराने का झांसा देकर करीब दो लाख रुपये भी लिए।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि ने बताया कि शिकायत के आधार पर यशोवर्धन के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है

●फर्जी इंटेलिजेंस अफसर बनकर धोखाधड़ी का आरोप

विभिन्न मदों में उनसे कुल 15 लाख रुपये लिए गए, लेकिन न तो फंडिंग दिलाई गई और न ही अन्य वादे पूरे किए गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उन्हें धोखाधड़ी का संदेह हुआ और उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो यशोवर्धन ने उनसे संपर्क समाप्त कर दिया तथा उनके मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिए। राजपुर थाना प्रभारी पीडी भट्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यशोवर्धन का नाम इससे पहले भी विवादों में सामने आ चुका है। आरोपी पर पूर्व विधायक प्रणव सिंह चौंपियन के बेटे से जुड़े एक विवाद में भी खुद को वरिष्ठ अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करने के आरोप लगे थे। हालांकि अभी तक आरोपी की पुलिस गिरफ्तारी नही कर सकी है।

युवक की गला रेतकर हत्या, दो महिलाएं घायल

हमारे संवाददाता

अल्मोड़ा। रानीखेत तहसील क्षेत्र के दूरस्थ ऐना गांव में बीती शाम अज्ञात हमलावर ने पास के सिमोली गांव निवासी एक युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। बीच-बचाव के लिए आईं युवक की बुआ सहित दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। यह युवक मेरठ में पढ़ाई करता था और कुछ समय से सेना में अग्निवीर की भर्ती की तैयारी भी कर रहा था।

जानकारी के अनुसार, सिमोली गांव निवासी 20 वर्षीय सागर पुत्र चंदन सिंह यहां ऐना गांव में अपनी बुआ जानकी देवी के यहां आया हुआ था। बताया जा रहा है कि बीती देर शाम एक अज्ञात हमलावर घर में घुस आया और सागर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। बाद में हमलावर ने सागर की गला रेतकर हत्या कर दी।

हमले के दौरान बीच-बचाव के लिए आईं सागर की बुआ जानकी देवी और जानकी की सास साबुली देवी को चाकू मारकर घायल कर दिया और फरार हो गया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को उपचार के लिए उप जिला अस्पताल रानीखेत ले जाकर भर्ती कराया है। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। कोतवाल भुवन जोशी ने बताया कि हमलावर कौन था और क्यों वारदात को अंजाम दिया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अभी हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। हमलावर की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द खुलासा किया जाएगा।

दून वैली मेल

संपादकीय

हरित ईंधन की जल्दबाजी

देश में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनाल मिश्रण को स्वच्छ ऊर्जा, विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नीति के उद्देश्य निश्चित रूप से सराहनीय हैं। लेकिन जब कोई राष्ट्रीय नीति सीधे करोड़ों वाहन मालिकों की जेब और उनके वाहनों की कार्यक्षमता से जुड़ती हो, तब केवल लक्ष्य नहीं, उसके क्रियान्वयन की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक वाहन मालिकों ने शिकायत की है कि ई20 पेट्रोल भराने के बाद उनके वाहनों की माइलेज घटी, इंजन की कार्यक्षमता प्रभावित हुई या रखरखाव की समस्या बढ़ी। दूसरी ओर, वाहन निर्माता कंपनियां लगातार यह स्पष्ट कर रही हैं कि सभी वाहन ई20 के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। पुराने माडलों में एथेनाल की अधिक मात्रा ईंधन प्रणाली के कुछ हिस्सों पर अतिरिक्त प्रभाव डाल सकती है, जबकि ई20-अनुकूल वाहनों को विशेष रूप से इस मिश्रण को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। यदि देश की सड़कों पर अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे वाहन चल रहे हैं जो पूरी तरह ई20-अनुकूल नहीं हैं, तो क्या उनके लिए पर्याप्त संक्रमण योजना तैयार की गई? क्या हर पेट्रोल पंप पर उपभोक्ता को स्पष्ट जानकारी मिलती है कि कौन-सा ईंधन उसके वाहन के लिए उपयुक्त है? क्या वाहन मालिकों को पर्याप्त जागरूक किया गया? सरकार का कहना है कि एथेनाल मिश्रण से प्रदूषण कम होगा, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटेगी और गन्ना उत्पादकों सहित कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा। यह तर्क मजबूत हैं और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी। लेकिन किसी भी नीति की सफलता तब मानी जाती है जब उसके लाभों का बोझ आम नागरिक पर अनुचित रूप से न पड़े। यदि किसी उपभोक्ता को वाहन निर्माता की सलाह के विपरीत ईंधन का उपयोग करना पड़ता है, या उसे यह जानकारी ही नहीं मिलती कि उसका वाहन किस ईंधन के लिए उपयुक्त है, तो समस्या नीति की मंशा में नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन और संवाद में है। हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण आवश्यक है, लेकिन यह संक्रमण भरोसे और स्पष्ट जानकारी के साथ होना चाहिए। इस मुद्दे का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सभी शिकायतों का कारण केवल ई20 हो, ऐसा निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं होगा। वाहन की उम्र, रख-रखाव, इंजन की स्थिति और निर्माता के तकनीकी मानक भी प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, तेल विपणन कंपनियां और वाहन निर्माता मिलकर पारदर्शी तकनीकी अध्ययन सार्वजनिक करें ताकि भ्रम और अफवाहों की जगह तथ्यों पर आधारित चर्चा हो। आज जरूरत किसी नीति का विरोध या समर्थन करने की नहीं, बल्कि उपभोक्ता के विश्वास की रक्षा करने की है। यदि ई20 भविष्य का ईंधन है, तो उसके लिए वर्तमान के करोड़ों वाहन मालिकों को असमंजस में नहीं छोड़ा जा सकता। हर पेट्रोल पंप पर स्पष्ट सूचना, वाहन-वार अनुकूलता की आसान जानकारी, तकनीकी सहायता और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। हरित भारत का सपना तभी सफल होगा, जब पर्यावरण के साथ-साथ आम नागरिक की जेब और उसके वाहन का भी समान सम्मान किया जाएगा। ऊर्जा परिवर्तन की असली सफलता आंकड़ों से नहीं, बल्कि उस भरोसे से तय होगी जिसके साथ नागरिक अपनी गाड़ी में अगली बार ईंधन भरवाएगा।

उत्तराखंड कांग्रेस के 'सारथी' बैकफुट पर

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं, संगठन को सक्रिय करने की कवायद चल रही है और सत्ता परिवर्तन का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल राजनीतिक गलियारों में लगातार तैर रहा हैकृकांग्रेस के सबसे अनुभवी चेहरों में गिने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरदा यानी हरीश रावत अपेक्षाकृत कम सक्रिय क्यों दिखाई दे रहे हैं? उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में हरीश रावत लंबे समय तक सबसे प्रभावशाली जननेता रहे हैं। चुनावी रणनीति से लेकर कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने तक उनकी भूमिका अहम मानी जाती रही है। ऐसे में चुनावी माहौल के बीच उनकी सीमित सार्वजनिक सक्रियता को लेकर तरह-तरह की राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बड़े नेताओं के दौरे, संगठनात्मक बैठकों और चुनावी तैयारियों का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं का एक वर्ग मानता है कि यदि हरीश रावत भी पहले की तरह लगातार जनसभाओं, पदयात्राओं और संगठनात्मक अभियानों में सक्रिय दिखाई दें, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल और मजबूत हो सकता है। हालांकि कांग्रेस के भीतर यह भी राय है कि पार्टी अब सामूहिक नेतृत्व के माडल पर आगे बढ़ रही है और चुनाव किसी एक चेहरे के बजाय पूरी टीम के दम पर लड़ना चाहती है।

हरीश रावत की सीमित सक्रियता को

◆2027 की लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल बन रही है गैरहाजिरी

◆उत्तराखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की सक्रियता बढ़ी

◆पूर्व सीएम हरदा की सीमित मौजूदगी पर हो गई चर्चा तेज

भाजपा भी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस अपने सबसे बड़े जनाधार वाले नेता की भूमिका को लेकर स्पष्ट नहीं है। सत्ता पक्ष इसे कांग्रेस के अंदर नेतृत्व को लेकर असमंजस का संकेत बताता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पार्टी में सभी वरिष्ठ नेताओं की भूमिका तय है और चुनावी समय आने पर हर नेता अपनी जिम्मेदारी निभाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समय के साथ हरीश रावत की भूमिका में बदलाव आया है। पहले वह आंदोलन, जनसंपर्क और चुनावी अभियान का सबसे प्रमुख चेहरा होते थे, जबकि अब संगठन में नई पीढ़ी के नेताओं को भी आगे बढ़ाने की कोशिश दिखाई दे रही है। इसके बावजूद यह भी सच है कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर कुमाऊं और गढ़वाल के अनेक इलाकों में आज भी हरीश रावत की व्यक्तिगत पहचान और जनसंपर्क क्षमता को कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक पूंजी माना जाता है।

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा की मजबूत संगठनात्मक मशीनरी का मुकाबला करना है। ऐसे में अनुभवी नेतृत्व और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि हरीश रावत चुनावी अभियान में अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो इसका असर कार्यकर्ताओं के उत्साह और चुनावी संदेश दोनों पर पड़ सकता है। दूसरी ओर यदि पार्टी पूरी तरह नए नेतृत्व और सामूहिक रणनीति पर भरोसा करती है, तो उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वरिष्ठ नेताओं का अनुभव और जनाधार चुनावी अभियान से अलग-थलग न पड़ जाए।

उत्तराखंड की राजनीति में एक कहावत अक्सर सुनाई देती है कांग्रेस का चुनाव और हरदा की चर्चा, दोनों अलग नहीं हो सकते। यही कारण है कि जैसे-जैसे 2027 का चुनाव करीब आएगा, हरीश रावत की भूमिका, उनकी सक्रियता और चुनावी रणनीति में उनकी भागीदारी पर राजनीतिक चर्चाएं और तेज होना लगभग तय है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि कांग्रेस यदि सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, तो उसे अपने अनुभवी नेतृत्व, संगठनात्मक मजबूती और नई राजनीतिक रणनीतिकृतीनों के बीच संतुलन बनाना होगा। उत्तराखंड की चुनावी बिसात पर यह संतुलन ही जीत और हार के बीच का सबसे महत्वपूर्ण अंतर साबित हो सकता है।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर

संवाददाता

देहरादून। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस अभी तक नाकाम साबित होती दिख रही है। पीडित परिवार का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है और पीडित परिवार को धमका रहा है इसके बावजूद कोतवाली पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है।

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत मालियान मौहल्ले में एक नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। जिसके बाद हिन्दूवादी संगठनों ने आरोपी की दुकान में तोडफोड करने के साथ ही कोतवाली का घेराव किया था। जिसके बाद से क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया था। लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया था। जिसके बाद पुलिस उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पायी है। वहीं पीडिता की मां का आरोप है कि उन्हें उत्तराखण्ड छोडने की धमकी दी जा रही है। जिससे पूरा परिवार भय में जीने को मजबूर है। इस सम्बन्ध में पीडिता की मां ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ एसपी देहात जया बलूनी से मिलकर अपनी पीडा बतायी। इस दौरान नाबालिग ने पूरे घटनाक्रम और उसके बाद परिवार पर पड रहे मानसिक दबाव की जानकारी दी। पीडिता की बात सुनकर वहां मौजूद लोग सकते में आ गये। परिवार के साथ पहुंचे स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद हुए बवाल व तोडफोड के बावजूद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नही होने

◆पीडित परिवार को धमकाने का आरोप

पर उसका मनोबल बढ रहा है। परिजनों का कहना है कि आरोपी के खुलेआम घुमने से परिवार हर समय दहशत में रहता है। उनका आरोप है कि आरोपी पक्ष लगातार समझौते के लिए दबाव बना रहा है। जिसके बाद एसपी देहात ने सम्बन्धित थाना पुलिस को पीडित परिवार की सुरक्षा के निर्देश दिये। जिसके बाद भी कोतवाली पुलिस ने मामले में गम्भीरता नहीं दिखायी। जहां पुलिस अधिकारी दावा करते है कि पीडित का न्याय दिलाना पुलिस की पहली प्राथमिकता है तो वहीं सम्बन्धित थाना चौकी प्रभारी अधिकारियों को दावों को हवा में उडाते हुए दिखायी दे रहे हैं। क्यों अधिकारी भी धरातल में आकर अपने दावों को परखने की जहमत नहीं उठाते हैं तो फिर कर्मचारी भी उनके दावों को पलीता लगाने से पीछे हटते दिखायी नहीं दे रहे हैं।

शहर कोतवाल का सरकारी फोन स्विच ऑफ

देहरादून (सं)। नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर जब शहर कोतवाल से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया तो उनको सरकारी फोन नम्बर 9411112829 स्विच आफ सुनायी दिया जो अपने आपमें एक सोचने का विषय है। उल्लेखनीय है कि शहर के बीचो बीच एक नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। जिसके बाद हिन्दूवादी संगठनों ने जमकर बवाल मचाने के साथ ही आरोपी की दुकान में तोडफोड के साथ ही कोतवाली का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। लेकिन घटना के बाद से आज तक पुलिस आरोपी को तो गिरफ्तार नहीं कर सकी ऊपर से आरोपी पीडित परिवार को धमकाने उनके यहां पहुंच रहा है।

इस मामले में जब शहर कोतवाल के सरकारी फोन नम्बर 9411112809 पर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया तो वह स्विच आफ मिला। जिसके बाद सोचने वाली बात है कि शहर कोतवाली क्षेत्र में इतना बडा कांड हो गया और कोतवाल स्विच आफ करके बैठे हैं तो क्या इससे भी बडी घटना का उनको इंतजार है?

उत्तराखंड में रुद्राक्ष उत्पादन की अपार संभावनाएं!

प्रतिनिधि

देहरादून। टिहरी गढ़वाल के विधायक किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने विश्व के प्रमुख रुद्राक्ष उत्पादक देश नेपाल का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड में रुद्राक्ष उत्पादन की व्यापक संभावनाएं जताते हुए 200 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है।

प्रतिनिधिमंडल में विधायक किशोर उपाध्याय के साथ रुद्राक्ष विशेषज्ञ प्रिंस अग्रवाल तथा वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लेखक डॉ. रमेश सिंह पाल शामिल थे। अध्ययन भ्रमण के दौरान नेपाल में रुद्राक्ष की उन्नत खेती, कृषि प्रबंधन, प्रसंस्करण, विपणन व्यवस्था, मृदा की विशेषताओं और उत्तराखंड में इसकी व्यावसायिक खेती की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन किया गया। अध्ययन के दौरान नेपाल के रुद्राक्ष उत्पादक क्षेत्रों की मिट्टी के नमूनों की प्रयोगशाला में जांच कर उनकी तुलना टिहरी, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून सहित गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी से की गई। जांच में पाया गया कि दोनों क्षेत्रों की मिट्टी में काफी समानता है, जिससे उत्तराखंड में रुद्राक्ष की सफल ▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

नंदादेवी मेले की तैयारियां तेज, मंदिर समिति ने डीएम से की मुलाकात

अल्मोड़ा (आरएनएस)। आगामी मां नंदादेवी महोत्सव एवं ऐतिहासिक नंदादेवी मेले की तैयारियों को लेकर मां नंदादेवी मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अंशुल सिंह से मुलाकात कर विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। समिति ने मेले के सफल एवं भव्य आयोजन के लिए प्रशासन से आवश्यक सहयोग देने का अनुरोध किया। समिति ने बताया कि नंदादेवी मेले में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और स्थानीय लोग शामिल होते हैं। इसे देखते हुए मेले की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन के साथ विस्तृत चर्चा की गई। मंदिर समिति ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संस्कृति विभाग एवं पर्यटन विभाग से स्वीकृत अनुदान की लंबित धनराशि शीघ्र जारी कराने की मांग भी उठाई। समिति का कहना था कि समय पर अनुदान मिलने से मेले की तैयारियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम बेहतर ढंग से आयोजित किए जा सकेंगे। समिति ने 19 सितंबर 2026 को महाअष्टमी के अवसर पर पूरे उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की भी मांग की। इस संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा गया। समिति का कहना है कि मां नंदादेवी उत्तराखंड की लोकआस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र हैं, इसलिए महाअष्टमी पर सार्वजनिक अवकाश घोषित होने से प्रदेशभर के श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना और मेले में शामिल होने का अवसर मिलेगा। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने समिति को आश्वस्त किया कि मां नंदादेवी मेले के सफल आयोजन में प्रशासन हरसंभव सहयोग करेगा।

आशाओं ने 18 हजार वेतन और राज्य कर्मचारी का दर्जा मांगा

बागेश्वर(आरएनएस)। आशा स्वास्थ्य कार्यकत्री संगठन के बैनर तले कार्यकर्त्रियों ने बुधवार को उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने राज्य कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम 18 हजार रुपये वेतन की मांग की। संगठन का कहना है कि देश में 11 लाख आशाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में टीकाकरण, स्वच्छता, जच्चा-बच्चा देखभाल, पल्स पोलियो, टीबी मुक्त भारत, डेंगू, कुष्ठ रोग जैसे तमाम काम कर रही हैं। ये सभी काम सरकारी और राज्य कर्मचारियों के हैं, लेकिन सरकारें आशाओं को अपना कर्मचारी मानने को तैयार नहीं हैं। संगठन की मांग है कि उन्हें तुरंत राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। ज्ञापन में आशाओं ने आठ प्रमुख मांगें रखी हैं। इसमें न्यूनतम 18 हजार मासिक वेतन, दुर्घटना पर पांच लाख और मृत्यु पर 10 लाख मुआवजा, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख एकमुश्त राशि शामिल है। इसके अलावा अनुभवी आशाओं को टीकाकरण का प्रशिक्षण, योग्यता धारी आशाओं की एएनएम पद पर पदोन्नति, सफल प्रसव पर यात्रा भत्ता या इलेक्ट्रिक स्कूटी और पल्स पोलियो के 150 रुपये को बढ़ाकर 800 रुपये प्रतिदिन करने की मांग की गई है। संगठन ने ज्ञापन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को भेजा है।

डॉक्टरों की कमी पर स्वास्थ्य सचिव से मिले ठुकराल

रुद्रपुर(आरएनएस)। जिला अस्पताल से चिकित्सकों के तबादलों के बाद प्रभावित हुई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की। उन्होंने रिक्त पदों पर तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द वैकल्पिक डॉक्टरों की तैनाती नहीं की गई तो जनहित में आंदोलन शुरू किया जाएगा। गुरुवार को राज्य सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव डॉ. विनय शंकर पांडेय और अपर सचिव (स्वास्थ्य) डॉ. सौरभ गहरवार से हुई बैठक में ठुकराल ने बताया कि हाल ही में जिला अस्पताल से 11 चिकित्सकों के स्थानांतरण के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं।डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कई मरीजों को बिना समुचित उपचार के लौटना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर जिला अस्पताल शहर के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों के लिए प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधिकांश मरीज इसी अस्पताल पर निर्भर हैं, लेकिन चिकित्सकों की कमी से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि स्थानांतरित चिकित्सकों के स्थान पर तत्काल वैकल्पिक चिकित्सकों की तैनाती कर उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जाए, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें और अस्पताल की व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके। ठुकराल ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर रिक्त पदों पर नए चिकित्सकों की नियुक्ति कर उन्हें कार्यभार नहीं सौंपा गया तो जिला अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना और आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

पहाड़ की 'पीड़ा' चुनावी 'हथियार'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस के इर्द-गिर्द घूमती रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा जोर पकड़ रही हैकृक्या राज्य में एक बार फिर क्षेत्रीय राजनीति लौट रही है? उत्तराखंड राज्य आंदोलन की विरासत अपने नाम से जोड़ने वाला उत्तराखंड क्रांति दल लगातार जनसंपर्क अभियान, पहाड़ के मूल मुद्दों और स्थानीय अस्मिता को केंद्र में रखकर खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश में जुटा है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि राज्य में यूकेडी के पक्ष में व्यापक चुनावी लहर बन चुकी है, लेकिन कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यदि पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच निरंतर सक्रिय रहने में सफल रहती है, तो वह कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है।

यूकेडी अपने पुराने राजनीतिक एजेंडे स्थायी राजधानी, सशक्त भू-कानून, मूल निवास, पलायन, बेरोजगारी, जल-जंगल-जमीन और पर्वतीय विकास को फिर से मजबूती से उठा रही है। पार्टी का तर्क है कि राज्य बनने के ढाई दशक बाद भी जिन मुद्दों के लिए उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, वह आज भी अधूरे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खाली होते गांव, सीमांत क्षेत्रों से पलायन, कृषि संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को लेकर यूकेडी भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साध रही है। पार्टी का कहना है कि राष्ट्रीय दल चुनाव के समय पहाड़ की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद प्राथमिकताएं बदल जाती हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता विरोधी माहौल बनने की स्थिति में सबसे अधिक फायदा अक्सर तीसरे विकल्प को मिलता है। यदि भाजपा और कांग्रेस दोनों के टिकट वितरण से असंतोष बढ़ता है, तो यूकेडी ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकती है। विशेषकर पर्वतीय सीटों पर स्थानीय चेहरों और क्षेत्रीय मुद्दों की पकड़ रखने वाले प्रत्याशी चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना सकते हैं। यदि यूकेडी सीमित सीटों पर भी प्रभावी प्रदर्शन करती है, तो कई निर्वाचन क्षेत्रों में जीत-

◆यूकेडी के उभार की आहट से बदले चुनावी समीकरण
◆भाजपा और कांग्रेस के बीच तीसरे विकल्प की तलाश
◆पहाड़ के मुद्दों पर फिर मुखर हुई उत्तराखंड क्रांति दल

हार का अंतर प्रभावित हो सकता है।

पार्टी युवाओं, बेरोजगारों और उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े परिवारों तक पहुंच बनाने का प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी यूकेडी अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। पार्टी का संदेश है कि उत्तराखंड की समस्याओं का समाधान स्थानीय सोच और स्थानीय नेतृत्व से ही संभव है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि केवल भावनात्मक मुद्दे चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। संगठन, संसाधन, मजबूत उम्मीदवार और बूथ स्तर की तैयारी किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

भले ही यूकेडी पूरे राज्य में सत्ता की मुख्य दावेदार न दिखाई दे, लेकिन कई सीटों पर उसका प्रभाव निर्णायक हो सकता है। यदि पार्टी 5 से 10 प्रतिशत तक वोट भी अपने पक्ष में खींचने में सफल रहती है, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के पारंपरिक गणित पर असर पड़ सकता है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि यदि चुनाव परिणाम त्रिशंकु स्थिति की ओर बढ़ते हैं, तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है।

उत्तराखंड की जनता ने राज्य आंदोलन के समय क्षेत्रीय नेतृत्व पर भरोसा जताया था, लेकिन बाद के वर्षों में यूकेडी संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व संकट और आंतरिक मतभेदों के कारण अपना जनाधार खोती चली गई। अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल जनता का विश्वास जीतना नहीं, बल्कि यह साबित करना भी है कि वह आंदोलन की विरासत से आगे बढ़कर आज के उत्तराखंड के लिए एक व्यवहारिक राजनीतिक विकल्प बन सकती है।

2027 का चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता का संघर्ष नहीं होगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दलों के लिए फिर से जगह बन रही है या नहीं। आने वाले महीनों में यूकेडी की संगठनात्मक सक्रियता, जनसंपर्क अभियान और स्थानीय मुद्दों पर उसकी पकड़ ही तय करेगी कि मौजूदा चर्चा चुनावी परिणामों में बदलती है या नहीं।

गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना के आवेदनों की हुई समीक्षा

हमारे संवाददाता

टिहरी। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त होमस्टे लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों की जिला स्तरीय समिति द्वारा स्क्रूटनी की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने आवेदकों से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनकी कार्ययोजना, प्रस्तावित होमस्टे, कक्ष निर्माण, कक्षों के नवीनीकरण तथा होटल एवं होमस्टे निर्माण संबंधी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि चयनित लक्ष्य के अंतर्गत सभी आवेदक जिला पंचायत से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करें, ताकि योजना का लाभ शीघ्र उपलब्ध

कराया जा सके। उन्होंने जिला पंचायत को भी सभी प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने तथा आवेदकों को हर संभव सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए। बैठक में आवेदक चंबा से प्रवीण कोठारी, नैनबाग से सुल्तान सिंह, थत्यूड़ से शोभना देवी, सोनी देवी, संजीत सिंह व सजनु सिंह, भिलंगना से रेवल सिंह, थौलधार से मनदीप सिंह, प्रतापनगर से किशन सिंह, चंबा से प्यार सिंह तथा थत्यूड़ से बलदेव सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। इन सभी ने अपने प्रस्तावों के तहत कक्ष निर्माण, कक्षों के नवीनीकरण तथा होटल एवं होमस्टे निर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल, जिला पर्यटन विकास अधिकारी सोबत सिंह राणा, अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग विशाल चौहान, अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) मनीष मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

महिलाओं को नजरअंदाज नहीं करने चाहिए जोड़ों के दर्द से जुड़े ये 5 चेतावनी भरे संकेत

जोड़ों से जुड़ी समस्याएं आजकल हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रही हैं, खासकर महिलाओं में यह आम हो गई हैं। कई बार महिलाएं जोड़ों का दर्द जैसे संकेतों को नजरअंदाज कर देती हैं, जिससे स्थिति बिगड़ती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे चेतावनी भरे संकेतों के बारे में बताएंगे, जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। इन संकेतों को पहचानकर आप समय पर इलाज करा सकती हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं।

सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न होना- अगर आपको सुबह उठते ही अपने हाथों या पैरों में अकड़न महसूस होती है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह गठिया या अन्य किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि समय पर इलाज मिल सके। सुबह की अकड़न अक्सर उम्र बढ़ने, असंतुलित आहार और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण होती है। सही समय पर पहचान और इलाज से आप इस समस्या से बच सकती हैं।

बैठते या उठते समय दर्द होना- बैठते या उठते समय अगर आपको दर्द होता है तो इसे हल्के में न लें। यह भी गठिया या अन्य किसी समस्या का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि सही इलाज मिल सके। बैठते या उठते समय दर्द होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे गलत तरीके से बैठना, शारीरिक गतिविधियों की कमी या चोट का सही इलाज न होना। सही समय पर इलाज से आप इससे बच सकती हैं।

चलने में दिक्कत होना- अगर आपको चलने में दिक्कत होती है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि सही इलाज मिल सके। चलने में दिक्कत होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे जोड़ों का कमजोर होना, पुराने चोट का सही इलाज न होना या शारीरिक गतिविधियों की कमी। सही समय पर पहचान और इलाज से आप इस समस्या से बच सकती हैं।

रात में सोते समय टांगों में दर्द होना- रात के समय सोते समय अगर आपकी टांगों में दर्द होता है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि सही इलाज मिल सके। रात के समय सोते समय दर्द होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे गलत गद्दे या तकिए का इस्तेमाल, पुराने चोट का सही इलाज न होना या शारीरिक गतिविधियों की कमी।

अचानक से वजन कम होना- अगर बिना किसी प्रयास के आपका वजन अचानक से कम हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि सही इलाज मिल सके। वजन कम होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे असंतुलित आहार, तनाव या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं।

क्या आपका थायराइड असंतुलित है? इन संकेतों से जानें

थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने वाले हिस्से में तितली के आकार की होती है और यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगर यह असंतुलित हो जाए तो इससे कई समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो यह बताते हैं कि आपकी थायराइड असंतुलित हो रही है और आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके।

वजन का बढ़ना या घटना- अगर आप बिना किसी बदलाव के अपने खान-पान या व्यायाम में बदलाव के वजन में उतार-चढ़ाव देख रहे हैं तो यह थायराइड असंतुलन का एक आम संकेत हो सकता है। कम थायराइड हार्मोन से ग्रस्त लोग वजन बढ़ने की शिकायत करते हैं, वहीं ज्यादा थायराइड हार्मोन से ग्रस्त लोग वजन घटने की समस्या का सामना करते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।

थकान महसूस होना- अगर आपको लगातार थकान महसूस हो रही है तो यह भी थायराइड असंतुलन का एक अहम संकेत हो सकता है। कम थायराइड हार्मोन से ग्रस्त लोगों को अक्सर खुद को थकान महसूस होती है, चाहे वे कुछ भी न करें, वहीं ज्यादा थायराइड हार्मोन वाले लोग थकान के साथ-साथ कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। इससे आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।

त्वचा का रूखा होना- अगर आपकी त्वचा सूखी और बेजान होती जा रही है तो समझ जाएं कि आपकी थायराइड असंतुलित हो रही है। कम थायराइड हार्मोन से ग्रस्त लोगों की त्वचा सूखी हो जाती है। वहीं ज्यादा थायराइड हार्मोन वाले लोगों की त्वचा पर पित्तीय समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा ज्यादा थायराइड हार्मोन वाले लोगों को बार-बार पसीना भी आता रहता है। इससे त्वचा की देखभाल जरूरी हो जाती है।

बालों का झड़ना- अगर आपको अपने सिर पर बालों की कमी महसूस हो रही है तो इसके लिए भी थायराइड असंतुलन जिम्मेदार हो सकती है। कम थायराइड हार्मोन से ग्रस्त लोगों के बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं, वहीं ज्यादा थायराइड हार्मोन वाले लोगों के बालों में पतलापन आ जाता है। इसके अलावा बालों के झड़ने से गंजेपन की समस्या भी हो सकती है। बालों की देखभाल पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है।

अनियमित या असामान्य माहवारी- अगर महिलाओं को माहवारी के दौरान असामान्य रक्तस्राव या दर्द का सामना करना पड़ रहा है तो यह भी थायराइड असंतुलन का एक आम संकेत हो सकता है। कम थायराइड हार्मोन से ग्रस्त महिलाओं को भारी रक्तस्राव का सामना करना पड़ सकता है, वहीं ज्यादा थायराइड हार्मोन से ग्रस्त महिलाओं को माहवारी के दौरान दर्द का सामना करना पड़ सकता है।

कॉकरोच पार्टी: क्या जनता सुरक्षा को लेकर चिंतित है?

देवेंद्र कुमार बुढाकोटी

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने हाल ही में कहा कि यदि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई, तो वे अमेरिका लौटने के लिए विवश होंगे। इस बयान ने कुछ समय के लिए चर्चा अवश्य बटोरी, लेकिन इससे एक अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण प्रश्न भी सामने आता है-आखिर भारतीय यह निर्णय किन आधारों पर लेते हैं कि उन्हें कहाँ रहना है? क्या केवल व्यक्तिगत सुरक्षा ही इसका कारण होती है, या फिर बेहतर अवसरों और उच्च जीवन-स्तर का आकर्षण अधिक प्रभावशाली होता है?

करोड़ों भारतीयों के लिए इसका उत्तर स्पष्ट है। सुरक्षा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन विदेश जाने का यह शायद ही कभी सबसे बड़ा कारण होती है। बेहतर शिक्षा, आकर्षक रोजगार, अधिक आय, प्रभावी सार्वजनिक सेवाएँ, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ शहर तथा अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमेय प्रशासनिक व्यवस्था लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मातृभूमि के प्रति प्रेम बना रहता है, लेकिन बेहतर भविष्य की आकांक्षा अक्सर उस पर भारी पड़ जाती है।

प्रवासन आज भारत के मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षाओं का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अनेक परिवारों के लिए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजना केवल शैक्षणिक निवेश नहीं, बल्कि स्थायी रूप से वहीं बस जाने की दिशा में पहला कदम होता है। माता-पिता अपनी जीवनभर की बचत इस आशा में खर्च कर देते हैं कि उनके बच्चे विदेश में रोजगार प्राप्त करेंगे, स्थायी निवास हासिल करेंगे और अंततः वहाँ की नागरिकता भी प्राप्त कर लेंगे। विवाह संबंध भी अब तेजी से इसी आकांक्षा से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे मामलों में जाति, समुदाय और यहाँ तक कि राष्ट्रीयता भी एक सुरक्षित एवं समृद्ध भविष्य की संभावना के सामने गौण हो जाती है।

हालाँकि भारतीय प्रवासन की कहानी केवल आज के छात्र वीज़ा तक सीमित नहीं है। औपनिवेशिक काल में हजारों भारतीयों

को गिरमिटिया श्रमिकों के रूप में मॉरीशस, फिजी, मलेशिया, गुयाना और सूरीनाम जैसे देशों के गन्ना, चाय, रबर और कॉफी के बागानों में काम करने के लिए भेजा गया था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी भाषा, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखा, जिसने आज के सशक्त भारतीय प्रवासी समुदाय की नींव रखी।

इसके बाद प्रवासन की नई लहरें बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुईं। पहले व्यापारी और छोटे उद्यमी विदेश गए, फिर विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य क्षेत्रों के पेशेवरों ने विदेशों का रुख किया। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में इंजीनियर, वैज्ञानिक, चिकित्सक और आईटी विशेषज्ञ आधुनिक भारतीय प्रवासन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। आज भारत विश्व के सबसे बड़े कुशल मानव संसाधन निर्यातकों में से एक है और भारतीय प्रवासी दुनिया के अनेक देशों में प्रभावशाली पदों पर कार्यरत हैं।

प्रवासन ने भारतीय समाज में भी व्यापक परिवर्तन किए हैं। बहुसांस्कृतिक वातावरण में रहने से विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों के बीच विवाहों को अधिक स्वीकार्यता मिली है। विदेशों में बसे भारतीयों के बीच जाति, धर्म और क्षेत्रीय पहचान की पारंपरिक सीमाएँ काफी हद तक कमजोर हुई हैं। ऐसे परिवर्तन अब धीरे-धीरे शहरी भारत में भी दिखाई देने लगे हैं। परिवारों की संरचना बदल रही है, तो उनके साथ-साथ रीति-रिवाज, भाषाएँ, सामाजिक संबंध और पारिवारिक नेटवर्क भी बदल रहे हैं। ये परिवर्तन भारत के उस सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित कर सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी शक्ति हमेशा परिवार और समुदाय रहे हैं।

फिर भी एक असहज प्रश्न बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) जैसे विश्वस्तरीय संस्थानों से प्रतिभाशाली छात्र निकलने के बावजूद भारत अपने सबसे मेधावी युवाओं को विदेश जाने से क्यों नहीं रोक पा रहा है? समस्या केवल विकसित देशों के आकर्षण की नहीं, बल्कि देश के भीतर पर्याप्त अवसरों के अभाव की भी है। यदि भारत अपनी प्रतिभा को देश में बनाए रखना चाहता है, तो उसे बेहतर शोध सुविधाएँ, योग्यता आधारित करियर उन्नति, पारदर्शी प्रशासन और वैश्विक स्तर की कार्य परिस्थितियाँ उपलब्ध करानी होंगी।

विदेश जाने की इच्छा को देशभक्ति की कमी नहीं माना जाना चाहिए। प्रवासी भारतीय आज भी भारतीय त्योहार मनाते हैं, अपने परिवारों से जुड़े रहते हैं, भारत में निवेश करते हैं और हर वर्ष अरबों डॉलर की धनराशि प्रेषण (रेमिटेंस) के रूप में भेजते हैं। उनका भावनात्मक संबंध भारत से उतना ही गहरा रहता है, भले ही उनका पेशेवर जीवन विदेशों में स्थापित हो।

इसलिए वास्तविक चुनौती किसी एक व्यक्ति को विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि सुशासन के माध्यम से आम नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आवश्यकता ऐसे भारत के निर्माण की है जहाँ प्रतिभाशाली नागरिक अवसर, सम्मान और आशा के कारण स्वयं यहीं रहना पसंद करें। आखिर राज्य और समाज से इससे अधिक और क्या अपेक्षा की जा सकती है?

(लेखक समाजशास्त्री हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र हैं तथा उनके शोध का उल्लेख नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन की पुस्तकों में किया गया है।)

शब्द सामर्थ्य -085

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं :

1. अनुचित, असत्य, जो ठीक न हो 3. बेवजह, बिनाकारण, व्यर्थ 4. हल्कीनींद, चकमा, धोखा 6. शक्कर पानी आदि का मीठा घोल 10. सोते से उठाना, सावधान करना, प्रदीप्त करना 11. चरमसीमा, सीमांत 14. पानी, आंसू 15. बैठा हुआ, विराजित 16. नृत्य 17. मृतप्राय, मृत्यु के करीब 19. जल, अम्बु 22. उपहार, भेंट 23. खबर, संदेश।

ऊपर से नीचे

1. गणपतिजी, 2. मांगनेवाला, पाने की इच्छा करने वाला 3. मिट्टी के रंग का, मटमैला 5. चला आता हुआ क्रम प्रथा, प्रणाली, रीति-रीवाज, 7. निशाचर, रात में विचरण करने वाला 8. पेड़ का धड़ा जहां से शाखाएं निकलती है, 9. मिठाई, खाने की मीठी चीज 12. शासन, गुप्तबात 13. श्रद्धा, स्त्री, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य 15. विपत्तिग्रस्त, दुखी, अभागा 16. प्रसिद्ध, नामवर 18. स्वप्न, ख्वाब 20. करीब, नज़दीक, समीप 21. सुबह, प्रातः, सबेरा।

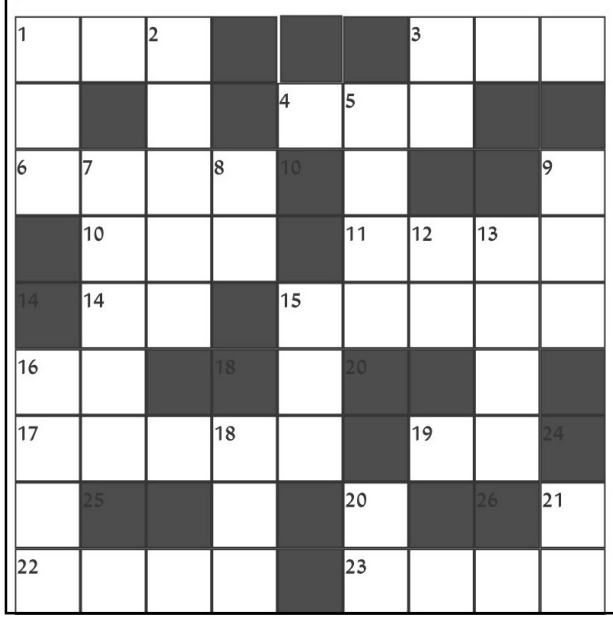

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 84 का हल

अ	भि	षे	क	■	प	स	■	■
जा	त	■	थ	प	थ	पा	ना	■
य	र	का	नी	■	भ्र	■	र	श्मि
ब	घा	र	■	क	ष्ट	प्र	द	■
■	त	ना	त	नी	■	र्व	■	ब
अ	■	मा	■	ज	मा	त	■	ल
स	जा	■	■	■	■	क	ज	रा
बा	■	बे	स	हा	रा	■	ग	म
ब	गु	ला	■	रा	ज	दू	त	■

आज का प्रशिक्षण, कल की स्मार्ट पुलिसिंगः चौबे

संवाददाता

टिहरी। तकनीक-सक्षम एवं दक्ष पुलिस बल तैयार करने के उद्देश्य से 08 एवं 09 जुलाई, 2026 को दो दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

एसएसपी श्वेता चौबे के निर्देशन में आरटीसी चम्बा में प्रशिक्षु आरक्षियों को आधुनिक संचार तकनीक, डायल-112 एवं सीसीटीवी प्रणाली का दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षु आरक्षियों को आधुनिक संचार प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी पुलिस रिस्पॉन्स के लिए तकनीकी रूप से दक्ष बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस संचार टीम द्वारा प्रशिक्षु आरक्षियों को रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली की विस्तृत जानकारी देते हुए एचएफ, वीएचएफ, लोअर बैंड एवं हायर बैंड वायरलेस सेटों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। साथ ही आरटी (रेडियो टेलीफोन) स्टेटिक सेट एवं हैंड सेट के संचालन, उपयोग, रखरखाव तथा संचार अनुशासन से संबंधित व्यवहारिक (प्रैक्टिकल) प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षु आरक्षियों को एमडीटी के प्रभावी उपयोग, इसके माध्यम से सूचनाओं के त्वरित, सुरक्षित एवं निर्बाध आदान-प्रदान, विभिन्न पुलिस इकाइयों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम से पुलिस कार्यों को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण सत्र में डायल-112 की संपूर्ण कार्यप्रणाली का भी विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। इसमें कॉलर द्वारा आपातकालीन कॉल किए जाने से लेकर कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होने, संबंधित थाना एवं पीआरवी द्वारा त्वरित कार्रवाई किए जाने तथा घटना के सफल निस्तारण के उपरांत सूचना क्लोज किए जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया से प्रशिक्षु आरक्षियों को अवगत कराया गया। इसके साथ ही सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के संबंध में भी विस्तृत जानकारी साझा की गई। प्रशिक्षुओं को सीसीटीवी प्रणाली की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरणों, विभिन्न प्रकार के कैमरों, उनकी कार्यप्रणाली तथा रिकॉर्डिंग के सुरक्षित संरक्षण एवं आवश्यकतानुसार उसकी जांच एवं विश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही आपदा एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में संचार व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने, त्वरित सूचना प्रसारण, विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने तथा राहत एवं बचाव कार्यों के दौरान संचार प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षु आरक्षियों को आधुनिक संचार उपकरणों के दक्ष उपयोग, तकनीकी ज्ञान के सतत उन्नयन तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित एवं समन्वित पुलिस रिस्पॉन्स सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभ्यास एवं प्रशिक्षण के महत्व पर विशेष बल दिया। टिहरी गढ़वाल पुलिस आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं सतत प्रशिक्षण के माध्यम से दक्ष, संवेदनशील एवं तकनीक-सक्षम पुलिस बल तैयार करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है, ताकि आमजन को सुरक्षित, त्वरित एवं विश्वसनीय पुलिस सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें।

मूसलाधर बारिश में भी एनसीसी शिविर में जारी रहा कठिन प्रशिक्षण

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। 84 उत्तराखंड बटालियन एनसीसी, रुड़की के तत्वावधान में क्वांटम विश्वविद्यालय, मंडावर में आयोजित दस दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में लगातार हो रही भारी वर्षा के बावजूद प्रशिक्षण गतिविधियाँ पूरे अनुशासन, उत्साह एवं जोश के साथ संचालित की गईं। प्रतिकूल मौसम भी कैडेट्स के उत्साह और जज्बे को कम नहीं कर सका।

शिविर के दौरान कैडेट्स को सैन्य प्रशिक्षण के विभिन्न विषयों का व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनमें ड्रिल, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट एवं बैटल क्राफ्ट, हथियारों की जानकारी, आपदा प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास तथा नेतृत्व क्षमता से संबंधित प्रशिक्षण प्रमुख रहे। प्रशिक्षकों ने विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की कला, धैर्य, अनुशासन एवं टीम भावना के महत्व पर विशेष बल दिया। लगातार बारिश के बीच भी कैडेट्स ने पूरे उत्साह के साथ सभी प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लिया। इस दौरान उन्हें यह संदेश दिया गया कि एक सच्चा सैनिक अथवा जिम्मेदार नागरिक परिस्थितियों से घबराता नहीं, बल्कि हर चुनौती का साहसपूर्वक सामना करता है। शिविर का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास तथा राष्ट्रसेवा की भावना का विकास करना है। शिविर कमांडेंट कर्नल जगदीश आलमिया ने कैडेट्स के उत्साह और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत मौसम में भी प्रशिक्षण जारी रखना एनसीसी कैडेट्स की दृढ़ इच्छाशक्ति, अनुशासन और राष्ट्रसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कैडेट्स को जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्षम बनाते हैं। शिविर के सफल संचालन में डिप्टी कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल अमन कुमार सिंह, कैंप एडजुटेंट कैप्टन सुशील कुमार आर्य, कैप्टन धर्म सिंह, फर्स्ट ऑफिसर (डॉ) पारस कुमार, फर्स्ट ऑफिसर नीरज नौटियाल, मीडिया प्रभारी सेकंड ऑफिसर अरुण कुमार, केयरटेकर दीपिका गोस्वामी सहित कई लोग शामिल रहे।

अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई एनसीओआरडी समिति की बैठक

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जनपद हरिद्वार में नशा मुक्त भारत अभियान एवं एनसीओआरडी के अंतर्गत मादक पदार्थों की रोकथाम, उपचार, पुनर्वास तथा जनजागरूकता को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में एनसीओआरडी (एनकॉर्ड) समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मादक पदार्थों की रोकथाम, अवैध तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों की मॉनिटरिंग तथा जनजागरूकता कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 में अब तक एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कई अभियोग दर्ज करते हुए हेरोइन (स्मैक), चरस, गांजा तथा प्रतिबंधित दवाइयों सहित अन्य मादक पदार्थों की बरामदगी की गई है। मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

बैठक में निर्देश दिए गए कि जनपद में संचालित संभावित क्लैंडेस्टाइन लैब की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही नारकोटिक्स, साइकोट्रॉपिक एवं अन्य प्रतिबंधित दवाओं (एनडीपीएस) की अवैध बिक्री रोकने के लिए औषधि

◆अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज
◆संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई जाएगी निगरानी

निरीक्षक नियमित निरीक्षण एवं सघन चेकिंग अभियान संचालित करेंगे। इसके अतिरिक्त सीबीएसई, आईसीएसई सहित सभी विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही जनपद में संचालित नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि 'नशा मुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत ग्राम पंचायतों, शहरी क्षेत्रों, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हुए अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे जनपद को नशा मुक्त बनाने के अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। बैठक के दौरान एसपी ट्रैफिक निशा यादव, सीओ सदर संजय शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर हरीश सिंह, एक्साइज इंस्पेक्टर दर्शन सिंह, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी दीपक कुमार, इंस्पेक्टर शांति कुमार गंगवार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

सीमांत गांवों को ट्रैकिंग होमस्टे अनुदान योजना से जोड़ने की मांग

उत्तरकाशी (आरएनएस)। सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को रोजगार का मजबूत आधार बनाने और पलायन पर अंकुश लगाने की मांग तेज हो गई है। गढ़वाल हिमालय ट्रैकिंग एवं माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने जिला प्रशासन से वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल पुराली, जसपुर, सुक्की और झाला गांवों को राज्य की ट्रैकिंग होमस्टे अनुदान योजना से जोड़ने की मांग की है।एसोसिएशन के अध्यक्ष जयेंद्र राणा का कहना है कि यह गांव पहले से ही केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल हैं। लेकिन पर्यटन सुविधाओं के अभाव में स्थानीय लोगों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

स्थाई हेलीपैड से त्वरित राहत एवं बचाव व्यवस्था होगी: जिलाधिकारी

हमारे संवाददाता

चम्पावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 'आदर्श चम्पावत' के विजन के अनुरूप जनपद में आपदा प्रबंधन, आपातकालीन राहत सेवाओं तथा पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से हवाई संपर्क सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य मानसून एवं आपदा के दौरान सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक त्वरित राहत एवं बचाव सेवाएं पहुंचाना तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत हवाई नेटवर्क तैयार करना है।

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जनपद के संवेदनशील एवं दुर्गम क्षेत्रों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। इससे आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी आएगी, वहीं पर्यटन गतिविधियों को भी नया आयाम मिलेगा।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में जनपद में स्थाई हेलीपैड विकसित किये जा रहे हैं, जिनमें पूर्व से संचालित एवं पूर्णतः क्रियाशील हेलीपैड भी शामिल हैं। साथ ही नए हेलीपैडों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिनमें एक हेलीपैड का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा शेष पर कार्य तेजी से जारी है। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में लोक निर्माण विभाग, चम्पावत द्वारा चूका क्षेत्र में हेलीपैड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट के अंतर्गत चमदेवल में हेलीपैड का निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। इसके अलावा सी एंड डीएस द्वारा रीठासाहिब, पाटी एवं देवीधुरा में नए हेलीपैडों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा प्रबंधन के तहत विकसित स्थाई हेलीपैडों में चम्पावत तहसील के जीआईसी तामली एवं जीआईसी मंच, पाटी तहसील के रीठासाहिब, पुनाकोट एवं जीआईसी देवीधुरा, तथा लोहाघाट तहसील के चमदेवल/बस्कुनी स्थित हेलीपैड शामिल हैं। इनका उद्देश्य आपदा अथवा अन्य आपात परिस्थितियों में त्वरित हवाई राहत एवं चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित स्थाई हेलीपैडों में जीआईसी पाटी, एबट माउंट (लोहाघाट), सर्किट हाउस चम्पावत तथा बनबसा स्टेडियम (टनकपुर) स्थित हेलीपैड शामिल हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग तत्काल राहत एवं बचाव कार्यों के लिए किया जा सकता है।

सड़क तो बना दी पुल बनाना भूल गया प्रशासन

उत्तरकाशी(आरएनएस)। दुर्बिल गांव की करीब 4.5० किलोमीटर लंबी खस्ताहाल सड़क की मरम्मत और मोटर पुल निर्माण की वर्षों पुरानी मांग एक बार फिर जोरशोर से उठी है। भाजपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के नेतृत्व में ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में ब्रीडकुल के मुख्य अभियंता एसके पाठक से मुलाकात की। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क तो वर्षों पहले बना दी गई लेकिन मोटर पुल का निर्माण नहीं होने से पूरी सड़क आज भी बेकार साबित हो रही है। पुल के अभाव में गांव तक वाहनों की आवाजाही संभव नहीं हो पाती जबकि रखरखाव के अभाव में 4.5० किमी लंबी सड़क भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। इससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की आवाजाही, खेती-बाड़ी और आपातकालीन परिस्थितियों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दीपक बिजल्वाण ने बताया कि हाल ही में दुर्बिल गांव के दौरे के दौरान ग्रामीणों ने सड़क और पुल की समस्या से अवगत कराया था। इसके बाद ग्रामीणों के साथ मुख्य अभियंता से मुलाकात कर उन्होंने साफतौर पर कहा कि जब तक मोटर पुल का निर्माण नहीं होता तब तक सड़क निर्माण पर खर्च की गई सरकारी धनराशि का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।उन्होंने जनहित को देखते हुए सड़क की तत्काल मरम्मत और मोटर पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। मुख्य अभियंता से मुलाकात करने वाले शिष्टमंडल में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सरजीत लाल, संदीप पंवार, विक्रम सिंह, जैरिया लाल, पूर्व प्रधान केदार सिंह, सोबत सिंह, चन्द्र सिंह, तारा सिंह आदि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर डीएम सख्त

अल्मोड़ा(आरएनएस)। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने गुरुवार को विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की विभागवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए लंबित मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आमजन की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों का केवल औपचारिक निस्तारण न किया जाए, बल्कि शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विभागों की शिकायतों के निस्तारण की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उन्हें तत्काल नोटिस जारी किए जाएं। साथ ही संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी नोटिस चस्पा किए जाएं, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और भविष्य में किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

सू- दोकू क्र.085

	9			2				1
		5	1				3	
7				9		8		5
	8		3		7		5	
2		7				1		3
	4			1			8	
6		2			9			
	5		7			3		
		8		5			6	7

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.84का हल

7	8	2	6	3	1	4	5	9
6	4	1	8	5	9	2	7	3
9	3	5	4	7	2		1	8
2	6	3	1	9	7	5	8	4
5	7	8	3	6	4	1	9	2
1	9	4	5	2	8	7	3	6
4	5	7	2	8	3	9	6	1
3	1	6	9	4	5	8	2	7
8	2	9	7	1	6	3	4	5

कांग्रेस की 'वीआईपी परेड' या संगठन बचाने की कवायद

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2०27 की आहट के साथ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के लगातार प्रस्तावित दौरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस में इन दिनों चल रही वीआईपी परेड का मकसद जनता के मुद्दों पर संघर्ष नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी और नेतृत्व विवाद को संभालना है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को उत्तराखंड की जनता की समस्याओं से अधिक अपने संगठन की अंदरूनी चुनौतियों की चिंता है। उनके अनुसार, प्रदेश में राष्ट्रीय नेताओं की लगातार मौजूदगी इस बात का संकेत है कि पार्टी अभी भी संगठनात्मक असंतोष और आपसी खींचतान से पूरी तरह उबर नहीं पाई है।

भाजपा का दावा है कि जिस दल का संगठन मजबूत होता है, उसे बार-बार दिल्ली से नेताओं को भेजकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अभी चुनाव लड़ने से पहले अपने ही नेताओं को एक मंच पर लाने की चुनौती से जूझ रही है। भाजपा यह भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के भीतर टिकट की संभावित दावेदारी, क्षेत्रीय गुटों की सक्रियता और नेतृत्व को लेकर अलग-अलग खेमों की खींचतान को शांत करने के लिए केंद्रीय

◆भाजपा का कांग्रेस पर तंज-जहां संगठन कमजोर, वहां बढ़ते हैं वीआईपी दौरे
◆दिल्ली के नेताओं की आवाजाही विकास के लिए नहीं, गुटबाजी संभालने के लिए
◆कांग्रेस नेताओं ने दिया भाजपा को जवाब यह चुनावी तैयारी है, गुटबाजी नहीं

नेताओं के दौरे बढ़ाए जा रहे हैं।

दूसरी ओर कांग्रेस इन आरोपों को राजनीतिक प्रचार करार दे रही है। पार्टी का कहना है कि राष्ट्रीय नेताओं के दौरे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने और विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा हैं। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा संगठनात्मक बैठकों को भी गुटबाजी का रंग देकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक दलों में समीक्षा बैठकें, रणनीति निर्माण और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद सामान्य प्रक्रिया है और इसे आंतरिक संकट बताना भाजपा की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी वर्ष नजदीक आते ही लगभग सभी बड़े दल अपने संगठन को सक्रिय करने के लिए वरिष्ठ नेताओं के दौरे बढ़ाते हैं। हालांकि, यदि किसी दल में पहले से मतभेदों की चर्चा हो, तो ऐसे दौरों को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जाता है। उत्तराखंड में कांग्रेस के सामने एक ओर भाजपा की मजबूत चुनावी मशीनरी है, तो दूसरी ओर उसे अपने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय और एकजुट बनाए रखने की चुनौती भी है। भाजपा इसी पहलू को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। स्पष्ट है कि उत्तराखंड की राजनीति अब चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है। भाजपा विकास, संगठन और सरकार के कामकाज को अपनी ताकत बताने में जुटी है, जबकि कांग्रेस सत्ता विरोधी मुद्दों को धार देने के साथ संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही भाजपा भी इन्हें राजनीतिक हथियार बनाकर यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले, फिर सरकार पर सवाल उठाए। फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में मुद्दों के साथ-साथ नैरेटिव की लड़ाई भी तेज हो चुकी है एक पक्ष इसे संगठन की मजबूती बता रहा है, तो दूसरा इसे गुटबाजी की मरम्मत। अंतिम फैसला, हमेशा की तरह, जनता करेगी।

रोटना है 'खुशी' बांटने की पहाड़ी 'परंपरा'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। आधुनिक जीवनशैली और बाजार की चकाचौंध में उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन धीरे-धीरे लोगों की थाली से गायब होते जा रहे हैं। इन्हीं में एक है रोटना पहाड़ की रसोई में बनने वाला ऐसा पारंपरिक पकवान, जिसकी मिठास केवल स्वाद में नहीं, बल्कि संस्कृति, अपनत्व और लोकजीवन में भी घुली हुई है। एक समय था जब गांव में किसी के घर शुभ कार्य होता, नई फसल कटती, पूजा-अर्चना होती या मेहमान आते, तो रसोई में सबसे पहले रोटना बनाया जाता था। यह केवल भोजन नहीं, बल्कि खुशी बांटने की परंपरा थी।

रोटना गेहूं के आटे से बनाया जाने वाला पारंपरिक मीठा व्यंजन है। इसमें गुड़ या शक्कर, देसी घी और स्थानीय स्वाद के अनुसार सौंफ, इलायची या अन्य घरेलू सामग्री मिलाई जाती है। इसे मोटे आकार में तवे या धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसकी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। पहाड़ की महिलाएं बताती हैं कि रोटना केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि परिवार के साथ बैठकर खाने और बांटने की संस्कृति का हिस्सा था। पहाड़ के गांवों में रोटना जन्मोत्सव, नामकरण, विवाह, इगास, हरेला और अन्य शुभ अवसरों पर बनाया जाता रहा है। खेतों में मेहनत के बाद गर्म रोटना और ताजा घी का स्वाद आज भी बुजुर्गों की यादों में बसा हुआ है। पहले जब बाजार से मिठाइयां आसानी से उपलब्ध नहीं थीं, तब रोटना ही

◆पहाड़ की रसोई का अनोखा भूला-बिसरा स्वाद
◆रोटना आज भी रिश्तों में घोलता रहता है मिठास
◆न घी से टपकती मिठाई और न बाजार की चमक
◆हर पर्व और शुभ अवसर की पहली पसंद रोटना

मेहमाननवाजी का सबसे सम्मानजनक व्यंजन माना जाता था।

आज गांवों से पलायन, संयुक्त परिवारों का टूटना और फास्ट फूड संस्कृति के बढ़ते प्रभाव ने रोटना जैसे पारंपरिक व्यंजनों को पीछे धकेल दिया है। नई पीढ़ी के कई युवाओं ने इसका नाम तो सुना है, लेकिन स्वाद कभी चखा ही नहीं। बुजुर्गों का कहना है कि पहले बच्चों को रोटना बनाना भी सिखाया जाता था, लेकिन अब यह कला धीरे-धीरे घरों से गायब होती जा रही है। यदि रोटना पारंपरिक तरीके से स्थानीय अनाज, गुड़ और सीमित घी के साथ बनाया जाए, तो यह पैकेज्ड मिठाइयों की तुलना में अधिक पौष्टिक विकल्प हो सकता है। स्थानीय अनाज और गुड़ ऊर्जा के साथ पारंपरिक स्वाद भी देते हैं।

पहाड़ में ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे संस्कृति तेजी से विकसित हो रही है। ऐसे में रोटना जैसे पारंपरिक व्यंजन पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं, जिस तरह अन्य राज्यों ने अपने पारंपरिक खाद्य पदार्थों को पर्यटन की पहचान बनाया है, उसी तरह रोटना भी उत्तराखंड की पाक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक बन सकता है। पहाड़ की पहचान केवल हिमालय, मंदिरों और प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं बनती, उसकी असली पहचान गांवों की रसोई में बसती है। रोटना उसी विरासत का स्वाद है, जिसे हमने आधुनिकता की दौड़ में पीछे छोड़ दिया। यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को केवल मोबाइल और माल की संस्कृति देंगे, तो वे शायद यह कभी नहीं जान पाएंगे कि पहाड़ की असली मिठास किसी महंगी मिठाई में नहीं, बल्कि मां के हाथों से बने एक साधारण रोटना में बसती थी।

पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत को बचाना है तो केवल लोकगीत और लोकनृत्य ही नहीं, रसोई की इस अमूल्य परंपरा को भी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। क्योंकि स्वाद भी इतिहास होता है, और रोटना उस इतिहास का मीठा अध्याय है।

यमुनोत्री मार्ग पर आया मलबा!

हमारे संवाददाता

उत्तरकाशी। सयानाचट्टी (यमुनोत्री मार्ग) पर आज सुबह भारी मलबा आने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे कई श्रद्धालु मार्ग में फंस गए। घटना की सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ पोस्ट बड़कोट से मुख्य आरक्षी दुर्गेश रतूड़ी के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम तत्काल आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों सहित घटनास्थल के लिए रवाना हुई। साथ ही एसडीआरएफ पोस्ट जानकीचट्टी से मुख्य आरक्षी राजेश कुमार के नेतृत्व में एक अन्य टीम भी मौके पर पहुंची।

बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर सड़क पूर्णत: अवरुद्ध होने के कारण एसडीआरएफ टीम द्वारा वैकल्पिक मार्ग पर सुरक्षित तरीके से रोप फिक्स की गई। इसके उपरांत जवानों ने अत्यंत सावधानी एवं कुशलता के साथ लगभग 100 यात्रियों को एक-एक कर सुरक्षित आर-पार कराया। एसडीआरएफ उत्तराखण्ड प्रदेश में आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी राहत एवं बचाव कार्यों के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

सरकार की हठधर्मिता: पेपर लीक का ठीकरा भी फोडा कांग्रेस के सिर

संवाददाता

देहरादून। पेपर लीक के मामले में भाजपा सरकार ने कांग्रेस को ही दोषी बताते हुए कहा कि कांग्रेस राज में पेपर लीक होते थे भाजपा राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी आम बात है लेकिन अपनी गलती को दूसरे की गलती साबित करना यह सही नहीं है। अभी हाल ही में भाजपा सरकार के कार्यकाल में नीट का पेपर लीक हो गया जिसके चलते एक युवती ने आत्महत्या तक कर ली। क्योंकि उसको अपना भविष्य अंधकार में दिखायी देने लगा था। इस ममाले में काफी शोर सुनायी दिया। लेकिन भाजपा सरकार उस शोर को सुनने को तैयार नहीं है और इस गलती में कांग्रेस को दोषी बता रही है। प्रदेश सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का यह बयान कि पेपर लीक कांग्रेस की सरकार में होता था हमारी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अब वह यह बताने को भी तैयार नहीं है कि कांग्रेस की सरकार के समय कौन से पेपर लीक हुऐ थे।

उत्तराखंड में रुद्राक्ष उत्पादन की...

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

खेती की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. रमेश सिंह पाल ने बताया कि उत्तराखंड में रुद्राक्ष आधारित एक मजबूत और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा सकता है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि उत्तराखंड के कई स्थानों पर जिन पेड़ों को रुद्राक्ष समझा जाता है, वे वास्तव में भद्राक्ष हैं। वास्तविक रुद्राक्ष Elaeocarpus ganitrus वृक्ष से प्राप्त होता है और इसका धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व अधिक माना जाता है। वहीं भद्राक्ष अन्य वृक्ष प्रजातियों से प्राप्त होता है और इसका बाजार मूल्य रुद्राक्ष की तुलना में काफी कम है। वर्तमान में भारत और चीन में बिकने वाला अधिकांश रुद्राक्ष नेपाल और इंडोनेशिया से आयात किया जाता है, जिसका कारोबार सालाना कई सौ करोड़ रुपये का है।

प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड में रुद्राक्ष की खेती की संभावनाएं तथा रणनीतिक विकास एवं विस्तार हेतु व्यापक कार्ययोजना विषय पर तैयार 200 पृष्ठों की रिपोर्ट 9 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री को सौंपी। रिपोर्ट में आयातित रुद्राक्ष पर निर्भरता कम करने, पर्वतीय किसानों की आय बढ़ाने, आध्यात्मिक पर्यटन और वेलनेस उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा उत्तराखंड को हिमालयी रुद्राक्ष के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द ही रुद्राक्ष खेती के रणनीतिक विकास एवं विस्तार के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करेगी। इसके लिए वन विभाग, जिला प्रशासन और कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से इसे धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रुद्राक्ष आधारित स्थानीय संपदा सृजन मॉडल पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। साथ ही यह राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण और उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत को नई पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

सरकार स्वयं जनता के द्वार पहुंचकर कर रही समस्याओं का समाधान : मुख्यमंत्री

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल, सहसपुर में सेवा, सुशासन एवं समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार जनसेवा शिविर में प्रतिभाग करते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शासन-प्रशासन को जनता के और अधिक निकट लाना है। सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि सरकार स्वयं उनके द्वार तक पहुंचकर सेवाएं उपलब्ध कराए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सुशासन का वास्तविक अर्थ संवेदनशील, जवाबदेह एवं जनकेंद्रित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि श्जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वारश अभियान ने शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत किया है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के प्रथम चरण में प्रदेशभर में 65 दिनों के दौरान लगभग 700 जनसेवा शिविर आयोजित किए गए, जिनमें पांच लाख से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। देहरादून जनपद में आयोजित 46 शिविरों में 60 हजार से अधिक नागरिकों ने सहभागिता की तथा लगभग 39 हजार लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया गया।

उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन एवं समर्पण के पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेशभर में जनसेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। 4 जुलाई से प्रारंभ हुए सेवा पखवाड़े में अब तक 64 हजार से अधिक नागरिकों ने प्रतिभाग किया है। इस दौरान प्राप्त 5,567 जनसमस्याओं में से 4,951 का समाधान सुनिश्चित किया गया है तथा 2,522 नागरिकों को विभिन्न प्रमाण-पत्रों एवं सेवाओं से लाभान्वित किए जाने की प्रक्रिया संचालित की गई है।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित शिविर में 01 हजार से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। इस अवसर पर पात्र लाभार्थियों को विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत प्रमाण-पत्र एवं अन्य सहायता वितरित की गई। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से आमजन को योजनाओं की जानकारी देने के साथ मौके पर ही आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ष्21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगाष का विजन आज तेजी से साकार हो रहा है। राज्य में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन, उद्योग, निवेश एवं हवाई संपर्क सहित प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार जी-20 बैठकों, राष्ट्रीय खेलों, शीतकालीन यात्रा तथा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे ऐतिहासिक आयोजनों का सफल आयोजन हुआ। राज्य की अर्थव्यवस्था निरंतर सुदृढ़ हो रही है तथा निवेश, उद्योग, स्टार्टअप और पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड नई पहचान बना रहा है।

सत्ता की 'राह' पर कांग्रेस का नया 'ब्लूप्रिंट'

◆आलोचना को छोड़ आंदोलन की राह पर कांग्रेस
◆केसी वेणुगोपाल ने फूंका सक्रियता का बिगुल
◆संगठन से सड़क तक लड़ाई तेज करने की तैयारी
◆राज्यों में जवाबदेही और मुद्दों की राजनीति पर जोर

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। आगामी विधानसभा चुनावों और अगले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए अपनी राजनीतिक रणनीति को नए सिरे से धार देना शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्पष्ट संकेत दिए कि कांग्रेस अब केवल सरकार की आलोचना तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संगठन, जनसंपर्क और जनआंदोलनों के जरिए मैदान में उतरकर राजनीतिक बढ़त हासिल करने का प्रयास करेगी। वेणुगोपाल के बयान को कांग्रेस के नए एक्शन प्लान का सार्वजनिक संकेत माना जा रहा है। पार्टी का संदेश साफ है कि चुनावी जीत केवल नारों से नहीं, बल्कि बूथ स्तर तक मजबूत संगठन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्ष से ही संभव होगी।

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अब वन साइज फिट्स आल की रणनीति छोड़कर राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप अभियान चलाएगी। जहां स्थानीय मुद्दे प्रभावी हैं, वहां क्षेत्रीय नेतृत्व को आगे रखा जाएगा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और संविधान की रक्षा जैसे विषयों को प्रमुखता दी जाएगी। वेणुगोपाल ने संगठनात्मक मजबूती को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए संकेत दिया कि निष्क्रिय इकाइयों की समीक्षा होगी और सक्रिय कार्यकर्ताओं को अधिक जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि जिला और ब्लाक स्तर तक संगठन चुनावी मोड में दिखाई दे।

कांग्रेस नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को भी साफ संदेश दिया है कि चुनावी वर्ष में केवल पद धारण करना पर्याप्त नहीं होगा, जो नेता और पदाधिकारी जनता के बीच सक्रिय रहेंगे, वही संगठन में आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संदेश पार्टी के भीतर अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कांग्रेस मानती है कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका जमीनी संगठन है। ऐसे में पार्टी अब उसी मोर्चे पर मुकाबले की तैयारी कर रही है। बूथ प्रबंधन, सोशल मीडिया नेटवर्क, जनसंपर्क अभियान और स्थानीय आंदोलनों को एक साथ जोड़कर चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। वेणुगोपाल ने यह भी संकेत दिया कि विपक्षी दलों के साथ राजनीतिक समन्वय और साझा मुद्दों पर सहयोग की संभावनाओं को भी पूरी तरह नकारा नहीं गया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाने पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है। कांग्रेस नेतृत्व की चिंता केवल चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि चुनाव जीतने की है। इसी कारण अब पार्टी की बैठकों में भाषणों से अधिक संगठनात्मक समीक्षा, बूथ रिपोर्ट, सदस्यता अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी का प्रयास है कि जनता के बीच यह संदेश जाए कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय सत्ता का मजबूत विकल्प बनने की तैयारी में है। आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस ने विशेष रणनीति बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। स्थानीय नेतृत्व को जनता के बीच अधिक सक्रिय रहने, सरकार को मुद्दों पर घेरने और संगठनात्मक समन्वय मजबूत करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी पार्टी सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश में जुटी है।

धामी के 'हैट्रिक' के दावे के सामने कांग्रेस 'ढर्रा'

◆उत्तराखंड कांग्रेस के सामने संगठन से लेकर नेतृत्व तक की अग्निपरीक्षा
◆नेताओं की ऊर्जा आपसी कलह में नहीं, जनता के बीच दिखनी चाहिए
◆अब संगठन में सक्रियता और जवाबदेही से ही तय होगा नेताओं का कद
◆जमीनी पकड़ और बूथ पर परिणाम देने वालों को ही मिल सकती है तवज्जो

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति इस समय दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए संगठन को फिर से खड़ा करने की चुनौती से जूझ रही है। दिल्ली से मिले संदेश ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के सामने स्पष्ट कर दिया है कि अब बयानबाजी नहीं, बल्कि बूथ स्तर पर परिणाम देने होंगे। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने संगठन की सक्रियता और जवाबदेही पर जिस तरह जोर दिया, उसका सीधा असर उत्तराखंड कांग्रेस पर पड़ना तय माना जा रहा है। प्रदेश में लंबे समय से नेतृत्व, गुटीय समीकरण और टिकट की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं चलती रही हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि नेताओं की ऊर्जा आंतरिक खींचतान में नहीं, बल्कि जनता के बीच दिखाई दे।

प्रदेश कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अलग-अलग शक्ति केंद्रों को एक मंच पर लाकर चुनावी अभियान को गति दे। यदि गुटीय राजनीति जारी रही तो भाजपा को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। इसके मुकाबले कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और स्थानीय युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केवल मुद्दे उठाना पर्याप्त नहीं होगा। इन मुद्दों को गांव-गांव और बूथ-बूथ तक पहुंचाने वाला मजबूत संगठन भी चाहिए।

उत्तराखंड की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां सरकारों के खिलाफ असंतोष समय-समय पर उभरता रहा है। लेकिन हर बार विपक्ष उसे चुनावी लाभ में बदल पाए, ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के सामने यही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। यदि पार्टी स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाती है, संगठन को सक्रिय करती है और टिकट वितरण में समय रहते स्पष्टता लाती है, तो मुकाबला रोचक हो सकता है। लेकिन यदि अंदरूनी खींचतान हावी रही तो सत्ता विरोधी भावना भी बिखर सकती है। वेणुगोपाल के संकेतों का एक असर टिकट वितरण पर भी पड़ सकता है। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं, बल्कि जमीनी सक्रियता, जनस्वीकार्यता और संगठनात्मक प्रदर्शन को भी महत्व देगा। इससे कई दावेदारों के लिए चुनौती बढ़ सकती है। 2027 के चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं की बड़ी संख्या और महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी चुनावी समीकरण बदल सकती है। कांग्रेस यदि इन दोनों वर्गों के लिए स्पष्ट एजेंडा और विश्वसनीय नेतृत्व प्रस्तुत करती है तो उसे राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। दूसरी ओर भाजपा भी अपने संगठन और सरकारी योजनाओं के दम पर इन्हीं वर्गों को साधने में जुटी हुई है। वेणुगोपाल का एक्शन प्लान उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक संदेश से अधिक एक संगठनात्मक चेतावनी भी है। अब यह देखना होगा कि प्रदेश नेतृत्व इसे कितनी गंभीरता से लागू करता है। आने वाले महीनों में कांग्रेस की सक्रियता, जनआंदोलन, सदस्यता अभियान और बूथ प्रबंधन ही तय करेंगे कि पार्टी 2027 में सत्ता की मजबूत दावेदार बनती है या फिर विपक्ष की भूमिका तक सीमित रह जाती है।

उत्तराखंड में 2027 की लड़ाई केवल भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं होगी, बल्कि संगठन बनाम असंतोष की भी होगी। भाजपा अपनी संगठित चुनावी मशीनरी और सरकार के कामकाज के आधार पर मैदान में उतरेगी, जबकि कांग्रेस को सत्ता विरोधी माहौल को जनसमर्थन में बदलने के लिए जमीन पर असाधारण मेहनत करनी होगी।

बदरीनाथ चढ़ावा प्रकरणः चोरी मामले में संदिग्ध फरार, मोबाइल बंद

हमारे संवाददाता

चमोली। बदरीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में निलंबित किए गए बीकेटीसी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल के लापता होने की खबर है। निलंबन के बाद से प्रमोद न तो बीकेटीसी के संपर्क में हैं और न ही उनका मोबाइल चालू है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामला सामने आने के बाद बीकेटीसी कर्मचारी प्रमोद ने अवकाश का आवेदन दिया था, जिसे प्रबंधन ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जोशीमठ कार्यालय में अटैच किया गया। लेकिन आदेश जारी होने के बाद से उन्होंने न तो जोशीमठ में ज्वाइनिंग दी और न ही कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई है।

बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने बताया कि प्रमोद से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है।

उल्लेखनीय है कि बदरीनाथ धाम में दानपात्र से चढ़ावा गायब होने का मामला सामने आने के बाद बीकेटीसी ने कार्रवाई करते हुए प्रमोद नौटियाल को निलंबित किया था। अब उनके अचानक गायब होने से विभाग में चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल बीकेटीसी इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार कर रहा है।

दून के दिल में बस गई फिल्म 'बेबी डू डाई डू'

संवाददाता

देहरादून। फिल्म बेबी डू डाई डू पिछले एक सप्ताह से लगातार हाउसफुल शो के साथ दर्शकों के अपार स्नेह की गवाह बन रही है। देहरादून के दर्शकों से मिले इसी अथाह प्रेम ने फिल्म की पूरी टीम को भावुक कर दिया। फिल्म के इंडिया दर्शन अभियान के अंतर्गत अभिनेत्री हुमा कुरैशी, अभिनेता रचित सिंह, मरुधर शेखावत, निर्देशक नचिकेत सामंत और निर्माता साकिब सलीम देहरादून पहुंचे। उन्होंने कहा कि देहरादून ने जिस अपनत्व के साथ बेबी डू डाई डू को स्वीकार किया, उसने पूरी टीम को भावुक कर दिया। यह केवल हाउसफुल शो की सफलता नहीं, बल्कि उन हजारों दिलों का विश्वास है जिन्होंने फिल्म के हर दृश्य, हर किरदार और हर भावना को अपना समझा। कलाकारों ने कहा कि दर्शकों की तालियां, मुस्कानें और आंखों में दिखाई देने वाला अपनापन उनके लिए किसी भी ट्रॉफी से बढ़कर है।

150 किलो गौमांस सहित 2 गौतस्कर दबोचे

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। मीट की दुकान में खुलेआम गौमांस काट रहे दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से 150 किलो गौमांस, पशु कटान के उपकरण व तराजू बरामद किया गया है।

जानकारी के अनुसार बीते रोज त्तराखण्ड गौवंश संरक्षण स्क्वाड, गढ़वाल रेंज हरिद्वार एवं कोतवाली पिरान कलियर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में गौतस्करी, गौहत्या एवं अवैध पशु कटान की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग एवं गश्त की जा रही थी। इस दौरान जब टीम कलियर स्थित तेलियों वाली मस्जिद के निकट मन्नवर उर्फ मन्ना की मीट की दुकान पर पहुंची। तो दुकान के अंदर दो व्यक्ति कथित रूप से मांस की काट-छांट

करते मिले। मौके से लगभग 150 किलो गौमांस, पशु कटान में प्रयुक्त उपकरण तथा कांटा-तराजू बरामद किया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि बरामद गौमांस दुकान संचालक मन्नवर द्वारा लाया गया था तथा उसे कलियर क्षेत्र में बेचने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से हिरासत में लिया व उनके खिलाफ सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियो के नाम अफरोज पुत्र नाजिर, निवासी निकट तेलियों वाली मस्जिद, वार्ड नं. 1, कलियर, कोतवाली कलियर, जनपद हरिद्वार व कलीम पुत्र वहीद, निवासी निकट कुरैशी वाली मस्जिद, वार्ड नं. 1, कलियर, कोतवाली कलियर, जनपद हरिद्वार बताये जा रहे है।

छात्र का बैग बस में छूटा, उत्तराखंड पुलिस ने लौटाया

संवाददाता

देहरादून। देहरादून में ईमानदारी और तत्परता की मिसाल पेश करते हुए उत्तराखंड पुलिस के सीपीयू कर्मियों ने एक छात्र का बस में छूटा बैग खोजकर उसे सकुशल वापस सौंप दिया। छात्र प्रेमनगर से सिटी बस के माध्यम से रेलवे स्टेशन आ रहा था। इसी दौरान उसका बैग बस में ही छूट गया। बैग में उसके महत्वपूर्ण दस्तावेज और जरूरी कागजात मौजूद थे। छात्र ने काफी खोजबीन की, जिसके बाद सीपीयू कर्मियों ने सक्रियता दिखाते हुए बैग को ढूंढ निकाला और छात्र को वापस सौंप दिया। बैग और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित वापस मिलने पर छात्र ने उत्तराखंड पुलिस, विशेषकर सीपीयू टीम का आभार व्यक्त किया।

वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत

हमारे संवाददाता

चम्पावत। मंच-तामली रोड पर स्थित घटोत्कच मंदिर के समीप आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार स्कूटी सवार युवक आज सुबह टिप्पर की चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि युवक का सिर लगभग पूरी तरह से कुचल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अपने परिवार का इकलौता पुत्र था। इस हृदयविदारक घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा

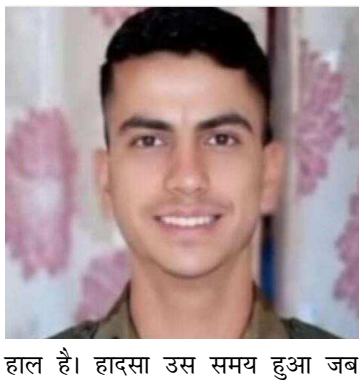

हाल है। हादसा उस समय हुआ जब चम्पावत से मंच तामली की ओर जा रहे टिप्पर की चपेट में दीपक जोशी की स्कूटी आ गई। मृतक की पहचान मूल रूप से मोराड़ी/बनलेख निवासी व हाल निवासी आरएफसी गोदाम के समीप दीपक जोशी (20) पुत्र मुरली जोशी के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। साथ ही टक्कर मारने वाले वाहन और उसके चालक की पहचान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जबकि क्षेत्र में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि टिप्पर चढ़ाई की ओर जा रहा था, जबकि स्कूटी ढलान की ओर आ रही थी। इसी दौरान स्कूटी अनियंत्रित होकर टिप्पर के पिछले पहिये की चपेट में आ गई।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकारः
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालयः दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोटः सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।